BUSINESS LINE, Delhi, 18.8.2024
Page No. 12, Size:(10.25)cms X (15.68)cms.

DGH upping data management to better handle E&P ecosystem

Richa Mishra
Hyderabad

GOING GREEN. Hydrocarbon Efficiency and New Energy Department is tasked with encouraging oil, gas operators to move towards net zero targets by adopting practices that enhance hydrocarbon efficiency

To create more transparency in data mining and accessibility as well as preparing itself for monitoring all types of energy sources, the Directorate-General of Hydrocarbons (DGH) is upgrading its National Data Repository (NDR) and also carving out a Hydrocarbon Efficiency and New Energy Department.

At successive roadshows held by the DGH before the exploration rounds, it has been found that investors want a more liberal regime in terms and stability in doing business here.

Also, a constant question to all the successive Director-Generals of DGH, the technical arm of the Ministry for Petroleum and Natural Gas that monitors exploration and production activities, has been why have the Exxons of the world still not made a mark in India's upstream space. What is it that they seek?

"A lot of things have been taken care of in the recently introduced Oilfields Regulation and Development (Amendment) Bill, 2024. Separately a working group for reserve-based funding — financing from banks — has also been constituted by the government," Pallavi Jain Govil, Director-General, DGH, told *businessline*.

While all these are happening on a real-time basis, the DGH is also working on NDR 2.0 Project. "Tenders have been floated for various packages for NDR 2.0 Project and tendering process is expected to be completed soon," she said.

NEW TOOLS, TECH

NDR has been disseminating data to various exploration and production operators, academia and government bodies and plays an important role in powering bidding rounds of exploration and production blocks/fields. Since NDR started operations in 2017, the hardware and software industry has undergone generational changes and new tools and technologies of data management have evolved, she said, adding that "Also, the existing NDR IT hardware has reached end-of-life stage."

Alongside, the DGH is also preparing itself for dealing with new energy sources. "For the purpose we have set up Hydrocarbon Efficiency and New Energy Department, dedicated to facilitate hydrocarbon efficiency, decarbonisation and energy transition by integrating new geological energies such as geothermal and natural hydrogen into current upstream activities," she said.

"This Department will significantly facilitate the exploration and production companies to achieve their Net Zero targets. Furthermore, these efforts will address critical environmental challenges, such as air pollution and climate change, by curbing carbon-dioxide, methane etc. gas emissions and promoting sustainable development in the energy sector," the DG elaborated.

The Department is tasked with encouraging oil and gas operators to move towards net zero targets by adopting practices that enhance hydrocarbon efficiency and incorporating new forms of geological energy. These new energy sources can serve as both supplemental and complementary to existing energy systems, thereby supporting the transition to a more resilient energy sector, she said.

INDIAN EXPRESS, Delhi, 18.8.2024
Page No. 13, Size:(12.20)cms X (4.60)cms.

CRUDE WATCH

OIL FALLS 2% TO END VOLATILE WEEK

New York: Oil prices settled down nearly 2% on Friday, little changed on the week with Brent crude below $80 a barrel, as investors tempered expectations of demand growth from top oil importer China. **REUTERS**

MILLENNIUM POST, Delhi, 18.8.2024

Page No. 2, Size:(4.23)cms X (16.85)cms.

Windfall tax on crude oil reduced to ₹2,100/tonne

NEW DELHI: The government has slashed windfall tax on domestically produced crude oil to Rs 2,100 per tonne, from Rs 4,600 per tonne with effect from Saturday.

The tax is levied in the form of Special Additional Excise Duty (SAED).

The SAED on the export of diesel, petrol and jet fuel or ATF, has been retained at 'nil'.

The new rates are effective from August 17, an official notification said.

India first imposed windfall profit taxes on July 1, 2022, joining a host of nations that tax supernormal profits of energy companies. The tax rates are reviewed every fortnight based on average oil prices in the previous two weeks. PTI

JANSATTA, Delhi, 18.8.2024
Page No. 10, Size:(6.98)cms X (9.60)cms.

कच्चे तेल पर सरकार ने उठाया कदम

अप्रत्याशित कर 4600 रुपए प्रति टन से घटाकर 2,100

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर (विंडफाल टैक्स) को 4,600 रुपए प्रति टन से घटाकर 2,100 रुपए प्रति टन कर दिया है। यह कर शनिवार से प्रभावी हो गया है। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है। डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर एसएईडी को 'शून्य' पर बरकरार रखा गया है। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि नई दरें शनिवार से प्रभावी हो गई हैं। भारत ने पहली बार एक जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ कर लगाया, जिससे वह उन देशों में शामिल हो गया जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण लाभ पर कर लगाते हैं। हर पखवाड़े पिछले दो सप्ताह में औसत तेल कीमतों के आधार पर कर दरों की समीक्षा की जाती है।

इससे पहले कच्चे तेल पर यह कर 7000 रुपए प्रति टन था, जिसे पिछले पखवाड़े में घटाकर 4600 रुपए प्रति टन किया गया। यह लगातार दूसरा ऐसा मौका है जब अप्रत्याशित कर के दर को घटाया गया है। डीजल और एटीएफ यानी जेट ईंधन पर कर को 'शून्य' पर बरकरार रखा गया है। दरअसल, तेल विपणन कंपनियों को अप्रत्याशित मुनाफा होने पर सरकार की ओर से अतिरिक्त कर लगाया जाता है, जिसे अप्रत्याशित कर कहते हैं। यह ऐसी कंपनियों पर लगता है जिन्हें लगातार बदलते हालात की वजह से अचानक उच्च मुनाफा हुआ है। भारत समेत कई देशों में तेल और ऊर्जा कंपनियों पर अप्रत्याशित कर लगाया जाता है। कच्चे तेल को लेकर फिलहाल दोहरा संकट है। रूस और यूक्रेन के बीच पहले से जारी जंग समेत पूर्वी एशिया के मौजूदा हालात को लेकर कच्चे तेल की आपूर्ति और उत्पादन को लेकर चिंता बनी हुई है। चीन, कच्चे तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है और कमजोर मांग का भी असर दिखता है।

> *डीजल,* पेट्रोल और जेट ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर एसएईडी को 'शून्य' पर बरकरार रखा गया है। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि नई दरें शनिवार से प्रभावी हो गई हैं।
>
> *भारत* ने पहली बार एक जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ कर लगाया, जिससे वह उन देशों में शामिल हो गया जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण लाभ पर कर लगाते हैं।

VEER ARJUN, Delhi, 18.8.2024
Page No. 11, Size:(19.31)cms X (16.01)cms.

सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित कर घटाकर 2,100 रुपए प्रति टन किया

नई दिल्ली, (भाषा)। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर (विंडफॉल टैक्स) को 4,600 रुपये प्रति टन से घटाकर 2,100 रुपये प्रति टन कर दिया है। यह कर शनिवार से प्रभावी हो गया है। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है। डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर एसएईडी को शून्य पर बरकरार रखा गया है। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि नई दरें 17 अगस्त दिन शनिवार से प्रभावी हो गई हैं। भारत ने पहली बार एक जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ कर लगाया, जिससे वह उन देशों में शामिल हो गया जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण लाभ पर कर लगाते हैं। हर पखवाड़े पिछले दो सप्ताह में औसत तेल कीमतों के आधार पर कर दरों की समीक्षा की जाती है।

VIRAT VAIBHAV, Delhi, 18.8.2024
Page No. 15, Size:(15.98)cms X (25.16)cms.

सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित कर घटाया

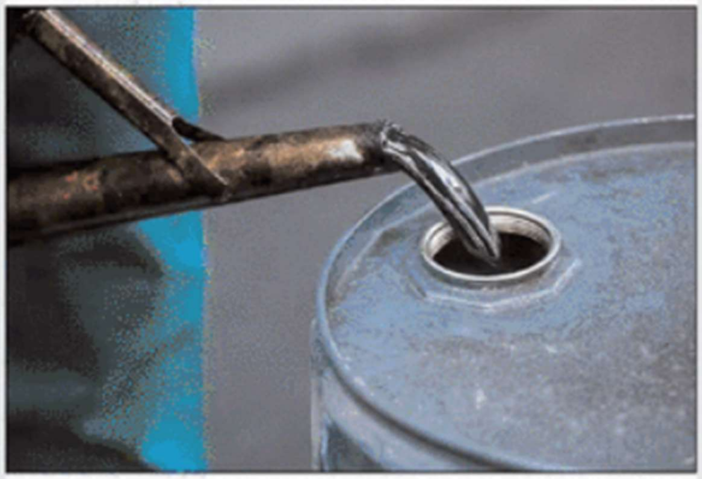

एजेंसी ■ नई दिल्ली

सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर (विंडफॉल टैक्स) को 4,600 रुपए प्रति टन से घटाकर 2,100 रुपए प्रति टन कर दिया है। यह कर शनिवार से प्रभावी हो गया है। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है। डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर एसएईडी को शून्य पर बरकरार रखा गया है। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि नई दरें 17 अगस्त दिन शनिवार से प्रभावी हो गई हैं। भारत ने पहली बार एक जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ कर लगाया, जिससे वह उन देशों में शामिल हो गया जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण लाभ पर कर लगाते हैं। हर पखवाड़े पिछले दो सप्ताह में औसत तेल कीमतों के आधार पर कर दरों की समीक्षा की जाती है।